

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

19.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00बजे

सी ए जी-सम्मेलन

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति ने लेखा परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और समय बचाने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में डिजिटलीकरण को एकीकृत करनेकी आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में आज राज्य वित्त सचिवों के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में संजय मूर्ति ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूरस्थ लेखापरीक्षा का लाभ उठाने, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों के लेखांकन को सुदृढ़ करने और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय निगरानी में सुधार पर चर्चा की। इस अवसर पर सी.ए.जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवित्त पर प्रकाशन के साथ-साथ एक इंटरैक्टिव डेटा डैशबोर्ड का भी अनावरण किया गया।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जी.एस.टी. में किए गए सुधारों से आम आदमी से लेकर व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आर्थिक सुधारों को नया आयाम दे रहे हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 28 फीसदी जीएसटी के तहत आने वाले 90 फीसदी उत्पादन को 18 फीसदी की जीएसटी में लाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों और कृषि उत्पादों का विशेष ध्यान रखा गया है और अनेक उत्पादों पर जीएसटी को खत्म किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था दुनियाभर में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है और वर्ष 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य है।

जीएसटी सुधार – ऑटो

कर ढांचे को सरल बनाने और नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की। नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। आज हम इन सुधारों के ऑटोमोबाइल उद्योग पर संभावित प्रभाव पर एक नज़र डालेंगे।

सराहना

मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के थुरल कस्बे के बछवाई गांव में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद भारतीय सेना, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा किए गए राहत व बचाव कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव दलों के अथक प्रयासों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त घरों से 13 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकाल कर उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

सेब पेटी

प्रदेश में 27 जून से 15 सितम्बर की अवधि के दौरान 20 किलो वज़न की कुल एक करोड़ 73 लाख 74 हजार 2 सौ 4 सेब पेटियां मंडियों में पहुंची हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये आंकड़ा पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान मंडियों में पहुंची सेब पेटियों से लगभग 50 लाख अधिक है। प्रवक्ता ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों को रिकॉर्ड समय में दुरुस्त किया गया है और राज्य सरकार सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए 24 घंटे काम कर रही है। शिमला जिले के पराला, सोलन के परवाणू और मंडी जिले जरोल में एचपीएमसी के फल प्रसंस्करण संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और यहां प्रतिदिन 4 सौ टन सेब का प्रसंस्करण हो रहा है।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ-नमस्कार.....